भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3503
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीएवाई-एनआरएलएम के तहत लखपति दीदी

3503. श्रीमती शांभवी:

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत "लखपति दीदी" पहल ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को किस प्रकार प्रभावित किया है और विशेषकर बिहार और महाराष्ट्र में इसकी निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ख) लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित प्रमुख कार्यनीतियां क्या हैं कि स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्य स्थायी रूप से 1 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय प्राप्त कर सकें;
- (ग) डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15,047 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ बजटीय आवंटन किस प्रकार एसएचजी सदस्यों की आजीविका को मजबूत करता है और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए कौन-कौन से नए उपाय किए जाएंगे; और
- (घ) स्व-सहायता समूह के सदस्यों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों के साथ अभिसरण की क्या भूमिका है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख) : दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) को जून, 2011 में शुरू की गई थी जिसे पूरे देश में (दिल्ली और चंडीगढ़ को

छोड़कर) कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना और उन्हें तब तक लगातार पोषित करना और सहायता प्रदान करना है, जब तक कि समय के साथ उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि न हो जाए और उनके जीवन स्तर में सुधार न हो जाए तथा वे अत्यंत गरीबी से बाहर न आ जाएं।

यह मिशन 28 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 742 जिलों के 7138 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कुल मिलाकर, 10.05 करोड़ महिलाओं को 90.87 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है। डीएवाई-एनआरएलएम सामुदायिक संस्थाओं को अपनी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने तथा मुख्यधारा के बैंक वित्त को आकर्षित करने के लिए अपना ट्रेक रिकॉर्ड बनाने हेतु स्थायी संसाधन बनाने के लिए निधियां उपलब्ध कराता है। इनमें प्रति स्वयं सहायता समूह 20,000 से 30,000 रुपये तक की परिक्रामी निधि तथा प्रति स्वयं सहायता समूह 2.50 लाख रुपये तक की सामुदायिक निवेश निधि शामिल है। महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण की प्रभावी लागत को कम करने के लिए, डीएवाई-एनआरएलएम बैंकों से ऋण पर स्वयं सहायता समूहों को ब्याज पर छूट प्रदान करता है। प्रदान की गई पूंजीकरण सहायता (परिक्रामी निधि और सामुदायिक निवेश निधि) की कुल राशि 48,290 करोड़ रुपये है। डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत नवंबर 2024 तक कुल संवितरित बैंक ऋण 9.71 लाख करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, सरकार ने स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी), आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई), महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी), महिला उद्यम त्वरण कोष (डब्ल्यूईएफ) के माध्यम से डीएवाई-एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और महिला उद्यमियों को वित्तीय रूप से सहायता देने के लिए कई कदम उठाए हैं।

लखपति दीदी पहल डीएवाई-एनआरएलएम का एक परिणाम है। लखपति दीदी एक स्वयं सहायता समूह सदस्य है, जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) है और औसत मासिक आय कम से कम 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) है, जो कम से कम 4 कृषि मौसमों और/या व्यवसाय चक्रों के लिए बनी रहती है। डीएवाई-एनआरएलएम स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को लखपति दीदी बनने के लिए नियमित रूप से जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। अब तक 1.15 करोड़ स्वयं सहायता समूह सदस्य लखपति दीदी बन चुकी हैं। जिनमें बिहार में 13,47,649 लखपति दीदियां और महाराष्ट्र में 10,04,338 लखपति दीदियां शामिल हैं।

ग) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15,047 करोड़ रुपये के बड़े हुए

बजटीय आवंटन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों की आजीविका को मजबूती प्रदान करना है। 15047.00 रुपए का बढ़ा हुआ प्रावधान अन्य बातों के साथ-साथ स्व-सहायता समूहों के लिए परिक्रामी निधि और सामुदायिक निवेश निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए है। इसके अलावा , बढ़े हुए बजट से डीएवाई-एनआरएलएम के तहत व्यापक कार्यकलाप आर्थिक सशक्तिकरण , कौशल विकास , सामाजिक समावेशन और समग्र सामुदायिक विकास के लिए एसएचजी महिलाओं में वित्तीय समावेशन और आय सृजन को बढ़ावा मिलेगा। यह बढ़ा हुआ आवंटन एसएचजी सदस्यों को 'लखपति दीदी' बनाने में भी सक्षम होगा।

(घ) इस मंत्रालय ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय , जनजातीय कार्य मंत्रालय , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आदि सहित विभिन्न प्रमुख मंत्रालयों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

केंद्रीय मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं जैसे नमो ड्रोन दीदी योजना , परंपरागत कृषि विकास योजना, सूक्ष्म उद्यमों के प्रधानमंत्री औपचारिकीकरण आदि के साथ यह अभिसरण न केवल इन कार्यक्रमों की भारत के दूरदराज के कोनों तक पहुंच सुनिश्चित कर रहा है बल्कि एसएचजी सदस्यों की आजीविका को मजबूती प्रदान करने में भी मदद कर रहा है। यह पहल "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोण की अवधारणा का अनुसरण करती है। इस सहयोग से यह भी सुनिश्चित होता है कि महिला एसएचजी सदस्यों को संसाधनों और अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला से लाभ प्राप्त हो , जिससे देश भर में उनका आर्थिक सशक्तिकरण , कौशल विकास और उनकी आजीविका में सुधार हो।